

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 969] No. 969] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 2003/कार्तिक 1, 1925 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2003/KARTIKA 1, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1230(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह को उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 24 सितम्बर, 2008 तक अर्थात् उस तारीख तक, जिसकी वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(3)/96-सीपीय]

सतवन्त रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2003

S.O. 1230(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, after consultation with the Chief Justice of India, hereby appoints Mr. Justice M.B. Shah, Retired Judge of the Supreme Court as President of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the date he assumes charge and up to the 24th day of September, 2008, i.e., the date on which he attains the age of seventy years.

[F. No. 1(3)/96-CPU]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.

3136 GI/2003